

आयोग की चिंता

ANALYSIS



 श्याम जाजू

सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल सही कहा है कि वह इस मुकाम पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी कानून पर रोक नहीं लगा सकता, क्योंकि इससे अराजकता पैदा हो जाएगी। दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के दूसरे ही दिन चुनाव प्रतिधियों की घोषणा हुई है और अब नियुक्ति संबंधी कोई भी विवाद चुनाव प्रक्रिया ही नहीं, पूरी राजनीति को जटिल बना सकता है। अतः अदालत ने कोई जल्दी न दिखाते हुए मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को करने का फैसला किया है, तब तक नई सरकार अपना काम शुरू कर चुकी होगी। दरअसल, विवाद इस बात पर है कि नए कानून के तहत चुनाव आयुक्तों के चयन से प्रधान न्यायाधीश को अलग कर दिया गया है, उनकी जगह एक केंद्रीय मंत्री चयन समिति में शामिल किए गए हैं। चुनाव आयोग में दोनों नई नियुक्तियां प्रधान न्यायाधीश की मर्जी के बिना हुई हैं। यह उचित है या नहीं, इस पर अंतिम फैसला गैरतलब होगा। फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय का रुख सरकार के अनुरूप ही है। आयुक्तों के चयन के संबंध में निश्चित कानून की कमी थी और अब जब सरकार ने कानून बना लिया है, तब इस कानून पर किसी भी तरह से सवाल उठाना सही नहीं है। हाँ, इस चयन प्रक्रिया के गुण-दोष पर न्यायालय विचार कर सकता है और यही कोशिश दिख रही है। न्यायालय को यह भी लगा है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए चयन समिति को उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि को समझने के लिए उचित समय दिया जाना चाहिए था। लोग अभी भूले नहीं हैं कि चयन में जल्दबाजी को लेकर चयन समिति के एक सदस्य कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी कड़ी आपत्ति जताई थी। चुनाव आयुक्तों की जल्द नियुक्ति जरूरी थी, लेकिन चयन की प्रक्रिया को लेकर कम से कम किसी सदस्य में असंतोष का भाव नहीं होना चाहिए। यह कोई नहीं चाहेगा कि कोई अयोग्य अधिकारी चुनाव आयुक्त नियुक्त हो, अतः आगे सावधानी बरतने की जरूरत है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, दीपांकर दत्ता और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है, मगर चयन में बरती गई कमियों की ओर इशारा भी कर दिया है और केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा है। चयन में ज्यादा पारदर्शिता और चयन समिति की बैठकों को गंभीरता से लेने की जरूरत है, ताकि किसी तरह की शिकायत की गुंजाइश न रहे। अदालत ने दोहराया है कि चुनाव आयुक्तों का चयन स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। आयुक्तों की पहचान उनके फैसलों के कारण ही होती है। यदि आयुक्त अपने फैसलों से निष्पक्ष चुनाव के पक्षधर दिखते हैं, तो इससे लोगों को खुशी भी होती है और देश में अच्छी राजनीति को बल भी मिलता है। इधर के दिनों में चुनाव आयोग पर लगातार उंगलियां उठाई जाती रही हैं। विशेष रूप से विपक्षी नेताओं को आयोग से बड़ी उम्मीद है। जिन आयुक्तों के चयन को चुनौती दी गई है, उनके लिए भी यह खुद को साबित करने का मौका है। आयोग से फिजूल शिकायत करने वालों को भी सजग रहना चाहिए, निष्पक्ष चुनाव सबकी जिम्मेदारी है।

ਕ੍ਰਾਦ ਮਿਤ੍ਰ

कुत्ता और समाज में उनके स्थान का लकर भारत में जाटल दुवधाए हैं। एक तरफ आवारा कुत्तों की समस्या है। देश भर में नागरिक अपनी आवासीय कॉलोनियों में धूमने वाले कुत्तों के हमले के बारे में शिकायत करते हैं, लेकिन इससे अभी तक इन कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए मौजूदा नगरपालिका कानूनों को लागू करने को लेकर कोई ठोस राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। दूसरी तरफ, पालतू कुत्तों से जुड़ी बिल्कुल ही अलग श्रेणी की चिंताएं को सामने आईं हैं। यहां वजह है कि केंद्र सरकार के एक मंत्रालय और दो हाईकोर्टों का ध्यान उन पर गया है। जिन सवालों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है उनमें एक यह है कि क्या कुत्तों की कुछ नस्लें स्वाभाविक रूप से दूसरों की तुलना में ज्यादा हँक्रूहँ हैं। कृषि मंत्रालय के पशु कल्याण और पशुपालन विभाग द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की है कि हँक्रूह कुत्तोंह की कुछ नस्लों को पालतू जानवर के रूप में रखने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। विभिन्न नागरिक समझौं की ओर से इन कुत्तों द्वारा लोगों पर हमले - कभी-कभी घातक भी - करने की शिकायत के बाद ऐसी समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर कुछ नस्लों पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया था। इनमें पिट बुल टेरियर, अमेरिकन स्टैफोर्डशार टेरियर, फिला ब्रासीलीरो, डोगो अर्जेंटीनो, अमेरिकन बुलडॉग, बोअरबोएल, कांगल, मध्य एशियाई शेफर्ड डॉग जैसे मिश्रित और संकर (क्रॉसब्रीड) नस्ल के कुत्ते शामिल हैं। इन नियमों को स्थानीय अधिकारियों द्वारा लागू किए जाने की उम्मीद है। जिन कुत्तों को पहले से ही पालतू जानवर के रूप में रखा गया है, उनका बंधाकरण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए कि आगे प्रजनन न हो। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में सरकार के इस आदेश पर उस समय रोक लगा दी जब कुछ याचिकाकर्ताओं ने यह आपत्ति जाती है कि सरकारी विभाग का कदम एकतरफा है और इसमें विशेषज्ञ निकायों की व्यापक धारा को शामिल नहीं किया गया है। केनेल क्लब ऑफ इंडिया, जो शुद्ध नस्लों को पंजीकृत करने वाली एक संस्था है, को इस निर्णय से समस्या हो सकती है। कुत्तों के स्वभाव से संबंधित सालों के अवलोकन और अंतर्विद्यि से यह पता चला है कि उनकी क्रूरता और आक्रामकता पर्यावरणीय व व्यवहारिक, दोनों कारकों का नतीजा है।

Social Media Corner

सच के हक में...



बिहार दिवस पर राज्य के अपने सभी परिवारजनों का हार्दिक अभिनन्दन! अपनी सांस्कृतिक विरासत और वैभव के लिए दुनियाभर में विशिष्ट पहचान रखने वाला हमारा यह प्यारा प्रदेश विकास के एक नए युग की ओर तेजी से अग्रसर है। मुझे विश्वास है कि विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में हमारे मेहनती और प्रतिभाशाली बिहारवासियों का अमूल्य योगदान रहने वाला है।

(प्रधानमंत्री द्वारा दिवसीय घोषणा)

बिहार दिवस पर राज्य के सभी निवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ। बिहार भारतीय संस्कृति और शिक्षा का ऐतिहासिक केंद्र रहा है। सकल्प शक्ति, कर्तव्यनिष्ठा और त्याग के लिए प्रसिद्ध बिहार के लोगों ने देश-विदेश में अपना स्थान बनाया है। यह राज्य प्रगति के मार्ग पर सदा अग्रसर रहे ऐसी मेरी मंगल कामना है।

(राष्ट्रपति द्वारा प्रदी मुर्म का 'एक्स' पर पोस्ट)

चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशों के महेनजर, आदर्श आचार सहिता लगे होने के कारण, फिलहाल ऑनलाइन संज्ञान की प्रक्रिया स्थगित की जाती है। इस संबंध में हुई असुविधा के लिए हमें खेद है।

(सीएम चमार्ह से ऐत का 'एक्स' पर पोस्ट)



श्रीराम मंदिर से बढ़ती समृद्धि और समरसता

पांच सौ वर्षों की प्रतीक्षा के बाद हुए श्रीराम मंदिर के पुनर्निर्माण ने न केवल भारतीय समाज की सांस्कृतिक और धार्मिक आधारशिला को मजबूत किया है बल्कि उसकी प्राण प्रतिष्ठा ने सम्पूर्ण देश में अभूतपूर्व समृद्धि और समरसता का मार्ग प्रशस्त किया है। आज पुनर्निर्मित भव्य राम मंदिर न केवल धार्मिक या ऐतिहासिक संदर्भ में महत्वपूर्ण बन गया है, बल्कि यह समृद्धि, समरसता, और एकता के प्रतीक के रूप में भी स्थापित हो गया है। राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया में समाज के सभी लोगों की भागीदारी ने एकता, सहयोग और सामाजिक समरसता की उसी मूल भावना का संवर्धन किया है जो प्रभु श्रीराम ने अहिल्या उद्घार तथा शबरी व निषादराज से प्रेम और मित्रता कर जगाई थी। मयार्दा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम ने सामाजिक समरसता और सशक्तिकरण का संदेश स्वयं के जीवन से दिया। उसी भावना से मंदिर के पूजन में इस्तेमाल हुए देश भर की हजारों पवित्र नदियों के जल व पावन तीर्थों की रज (मिट्टी) ने सम्पूर्ण भारत को भावनात्मक रूप से एकाकार कर दिया। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक पवित्र नदियों और पोखरों के जल तथा हर धर्म, संस्कृति, विचारधारा स्वरूप से जुड़े स्थलों जैसे संत रविदास के काशी स्थित जन्मस्थली, सीतामढ़ी के महर्षि वाल्मीकी आश्रम, विदर्भ के कचारगड़, झारखंड के रामरेखाधाम, मध्य प्रदेश के टट्ट्या भील की पुण्य भूमि, अमृतसर के श्री हरमंदिर साहिब, बाबा साहेब आबेंडकर के जन्मस्थान महू और दिल्ली के जैन लाल मंदिर आदि की मिट्टी मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा में प्रयुक्त हो देश में बढ़ती समरसता की नींव को

जबूत कर गई। राम मंदिर का निर्माण न केवल धार्मिक स्थल के रूप में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह का समरस, सहिष्णु समाज की नवधारणा का प्रतीक भी बन गया है। सामाजिक समरसता के साथ शीराम मंदिर के निर्माण ने सापूर्हिक भव और आर्थिक सशक्तिकरण का वह मार्ग भी प्रशस्त किया है जो समाज के हर वर्ग, हर धर्म, जाति और सम्प्रदाय को समान रूप से लाभ पहुंचाएगा। सदियों से आर्थिक रूप से पिछड़े पूर्वी उत्तर देश और उससे लगे क्षेत्रों का तो नाने काया पलट ही हो जायेगा जैसकी शुरूआत हो चुकी है। थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर पर सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के भार्यक विकास को एक नई गति नेलती दिख रही है जो देश के विकास में एक नई इंडिया और भारत के तीसरी सबसे बड़ी भार्यव्यवस्था बनने में महत्वपूर्ण योगदान करेगा। जातव्य है कि उत्तर देश राज्य ने अपने लिए पहले से 2027 तक राज्य को 1 खरब ट्रिलियन) की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखता है जो अब राम मंदिर के प्रतिष्ठापन के बाद अभय पूर्व ही साकार होता दिख रहा है। राम मंदिर के कपाट खुलने का बाद से ही उत्तर प्रदेश के ट्रिज्म सेक्टर (यूपी ट्रिज्म) में भूम देखने को मिल रहा है। भारत ने योगदान करीब 111 अरब हिंदुओं का मुख तीर्थस्थल बना अयोध्या नव अभूतपूर्व आर्थिक उछल रख रहा है। राम मंदिर में प्राण तिथि के एक दिन पहले यानी विवार 21 जनवरी स्टेट बैंक मॉफ इंडिया की एक रिपोर्ट कशित हुई जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य को अयोध्या के राम मंदिर और राज्य सरकार की अन्य पर्यटन जगतों के चलते भारी कमाई की सभावना बताई गई। रिसर्च से अनुमान जाहिर करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार व फाइनेंशियल ईयर 2025 में सिंगल अयोध्या से 20,000 से 25,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कमाई हो सकती है। विदेशी ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने एक रिपोर्ट में कहा था कि राम मंदिर का उद्घाटन और प्राचीन प्रतिष्ठान के बाद देश में बड़ा आर्थिक प्रभाव देखने को मिल सकता है। राम मंदिर के साथ भारत को एक नया पर्यटन स्थल मिल रहा है जिसकी वजह से देश में हर साल 50 मिलियन यात्री 5 करोड़ रुपये की ज्यादा पर्यटकों की संख्या इजाफा हो सकता है। निस्संदेश अयोध्या में राम मंदिर से भारत पर्यटन सेक्टर को बड़ा बूस्ट मिलेगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पर्यटन की बढ़ती संभावनाएं हैं। वित्त वर्ष 2019 देश की जीडीपी में पर्यटन सेक्टर का योगदान 194 बिलियन डॉलर का था। वहीं वित्त वर्ष 2030 यह बढ़कर 443 बिलियन डॉलर (करीब 36176 लाख करोड़ रुपये) पर पहुंचने का अनुमान है। पर्यटन में धार्मिक पर्यटन का बड़ा रोल है। भारत के लोकप्रिय धार्मिक केंद्रों में हर साल करोड़ों श्रद्धालु पहुंचते हैं। पर्यटन बढ़ने के अयोध्या में होटल, एयरलाइन, सेक्टर, हॉस्पिटलिटी सेक्टर, ट्रैवल, रेलवे, गाइड, पूजा सामग्री बेचने वाले दुकानदार, मूर्तियां बनाने वाले और ऐसी तमाम चीजों को बूस्ट मिलेगा। राम मंदिर ने निर्माण से पर्यटकों की संख्या बढ़ावा देने के साथ-साथ अयोध्या में निवेश बढ़ावा दिया है। निवेश बढ़ने से रोजगार व अवसर पैदा होंगे। माना जा रहा है कि अयोध्या में 20 हजार से 25 हजार नए रोजगार पैदा होंगे। रामलला के विराजमान होते ही अयोध्याम वैश्विक धार्मिक स्थवर और आध्यात्मिक टूरिस्ट हॉटस्पॉट बन गया है। दरअसल अयोध्या के निवेश के लिए एक नया हॉटस्पॉट

बन ही गया है। शहर में अब एक नया हवाई अड्डा टर्मिनल है जो 6,500 वर्ग मीटर में फैला है और हर साल दस लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करेगा। इस क्षमता को 60 लाख यात्रियों तक बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल की अपेक्षा 2025 तक है। भारत के हवाई वाहक, जैसे इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने प्रमुख शहरों को अयोध्या से जोड़ने वाली कई उड़ानें शुरू की हैं। अकासा एयर और स्पाइसजेट जैसी अन्य एयरलाइंस, अयोध्या के लिए हवाई यात्रा को बढ़ाने की योजना का अनावरण कर रही हैं। नए खुले हवाई अड्डे पर चार्टर्ड उड़ानों के लिए भी व्यवस्था की गई है। अधिकारी कार्यक्रम के दिन 100 से अधिक चार्टर्ड विमान हवाई अड्डे पर पहुंचे थे। इसके अलावा, चांपर सेवाएं अयोध्या को छह जिलों - गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज, मथुरा और आगरा से जोड़ेंगी। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन को 240 करोड़ रुपये में पुनर्निर्मित कर भव्य स्वरूप दिया गया है। भारतीय रेलवे ने 22 जनवरी के बाद अयोध्या के लिए 200 आस्था स्पेशल ट्रेनें भी शुरू की हैं। देश के विभिन्न हिस्सों को अयोध्या से जोड़ने वाली नित नई ट्रेनें प्रारम्भ हो रही हैं जिसका पूरे देश से राम मंदिर आने वाले श्रद्धालु उपयोग कर सकेंगे। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से भी सरयू को जोड़ने का कार्य चल रहा है। अयोध्या में 1,200 एकड़ में 2,180 करोड़ रुपये का ग्रीनफाइल्ड टाउन भी बनाया जा रहा है। इसमें मठों, आश्रमों, धर्मशालाओं और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अलग से भूखंड रखे जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटक वृद्धि की प्रत्याशा में भीड़भाड़ को कम करने के लिए परियोजना शुरू की। बुनियादी ढांचे के विकास में कनेक्टिंग हाई-वे, नवीनीकृत सड़कें, पानी और बिजली परियोजनाएं भी शामिल हैं अयोध्या को विश्व स्तरीय शहर में विकसित करने के लिए 30,500 करोड़ तक की कीमत वार्ल्ड लगभग 178 प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। इस बीच, राज्य सरकार का उद्देश्य विदेशी पर्यटकों और भारतीय नागरिकों दोनों की क्षमता का उपयोग करना है और "मुख्य केंद्र के रूप में अयोध्या के साथ रामायण सर्किट बनाना" है अयोध्या मास्टर प्लान 2031 के तहत, मंदिर शहर के बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए 85,000 करोड़ रुपये की परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं। राम मंदिर भारत के संपन्न आध्यात्मिक पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देगा सीएनबीसीटीवी 18 की रिपोर्ट के अनुसार, उद्घाटन के बाद से ही प्रतिदिन तीन से पांच लाख यात्री शहर में आ रहे हैं। न केवल होटल उद्योग, पर्यटन, रेस्टरां निर्माण परिवहन, डेयरी और कृषि उत्पादों जैसे बड़े व्यापार क्षेत्रों के बढ़ावा दिया जाएगा बल्कि छोटे व्यापारी जो फूल, फल, पेय अगरवुड अल्ट्या, कैंफर, धी आदि जैसी किसिमें बेच रहे हैं उन्हें लाभ मिलेगा। अयोध्या के रूप में एक नए धार्मिक पर्यटन केंद्र का निर्माण, बेहतर संयोजकता और बुनियादी ढांचे के साथ एक अर्थपूर्ण रूप से बड़ा आर्थिक प्रभाव पैदा कर सकता है इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, अयोध्या के राम मंदिर ने रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया है। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले ही आतिथ्य, यात्रा और पर्यटन ने अयोध्या में 20,000 नौकरियां पैदा की हैं।

। लखक, भाजपा के निवतमान
में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं।

पानी के बिना जीवन की कल्पना असंभव

प्र तिवार 22 मार्च का
दुनियाभर में लोगों में जल
संरक्षण और रखरखाव के
लेकर जागरूकता फैलाने के लिए
'विश्व जल दिवस' मनाया जाता
है। यह दिवस मनाए जाने के
घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1992 में
रियो द जेनेरियो में आयोजित
पर्यावरण तथा विकास का संयुक्त
राष्ट्र सम्मेलन में की गई थी। संयुक्त
राष्ट्र की उसी घोषणा के बाद
पहला विश्व जल दिवस 22 मार्च
1993 को मनाया गया था। यह दिवस
जल के महत्व को जानने, समझने
रहते जल संरक्षण को लेकर सचेतना
होने तथा पानी बचाने का संकल्प
लेने का दिन है। दरअसल जल
धरती पर मानव जीवन कंवर
बुनियादी जरूरतों में सबसे
महत्वपूर्ण तत्व है और वर्तमान में
पृथ्वी पर पेयजल की उपलब्धता से
जुड़े आंकड़ों पर नजर डालने से
स्पष्ट हो जाता है कि पानी की एक
एक बूंद बचाना हमारे लिए कितना
महत्वपूर्ण है। पानी की समस्या
भारत में भी लगातार गंभीर होती जा-
रही है, जिसका अंदाजा हाल वे

बगुलुरु जल सकट से असाना से लगाया जा सकता है। ऐसे में विश्व जल दिवस की महत्ता हमारे लिए भी कई गुना बढ़ जाती है। देश में हर साल जाने-अनजाने करोड़ों लीटर पानी बर्बाद हो जाता है। इसी बजह से कुछ वर्ष पूर्व विश्व जल दिवस के अवसर पर 22 मार्च के ही दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जल शक्ति अभियान: कैच द रेन की शुरूआत की थी और उस अभियान के तहत देश के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन के लिए नारा दिया गया था जहां भी गिरे, जब भी गिरे, वर्षा का पानी इकट्ठा करें। एक ओर जहां करोड़ों लोग विशेषकर गर्मी के मौसम में बूंद-बूंद पानी के लिए तरसते रहते हैं, वहाँ बारिश के मौसम में वर्षा जल का संरक्षण-संचयन नहीं होने के अभाव में प्रतिवर्ष लाखों गैलन पानी व्यर्थ बह जाता है। यदि इस पानी का संरक्षण कर लिया जाए तो देश की बड़ी आबादी की प्यास इसी पानी से बुझाई जा सकती है लेकिन चिंता की बात है कि देश में अभी तक

पा जल संरक्षण का लिए कहा तागरुकता नहीं दिखती। पर्यावरण संरक्षण पर हिन्दी अकादमी के बयोग से प्रकाशित पुस्तक प्रदूषण तक सांसे के अनुसार भारत में तल संकट बढ़ने का एक बड़ा नारण यही है कि हम वर्षा जल का छहत ही कम मात्रा में संरक्षण करते हैं। देश में प्रतिवर्ष करीब तीन जार अरब घन मीटर पानी की तरलरत होती है जबकि भारत में होने वाली वर्षा की मात्रा करीब जार अरब घन मीटर होती है जिकिन वर्षा जल संग्रहण के पर्याप्त बंध नहीं होने के कारण मामूली वर्षा जल का ही संग्रहण संभव नहीं हो पाता है। एक ओर जहां जाराइल जैसे देश में औसतन दस अंटीमीटर वर्षा होने के बावजूद भी वह इतने अन्न का उत्पादन करता है कि उसका नियर्त करने में भी सक्षम हो जाता है, वहीं दूसरी ओर भारत में औसतन पचास अंटीमीटर से भी ज्यादा वर्षा होने के बावजूद अन्न की कमी बनी रहती है। दरअसल नदियों-तालाबों जैसे वित्र माने जाते रहे जलस्रोतों को

जल में प्रदूषण की बढ़ती मात्रा तथा वर्षा जल संचयन का उचित प्रबंध होना भारत में जल संकट गहराया है। इसे नाने की मुख्य वजह बन रहे हैं। देश में आज के आधुनिक युग में लोगों की बहुत से इलाकों में लोगों का घर-दूर से पानी लाना पड़ता है। यह लंबी-लंबी कतारों में लगकच्चा कामचलाऊ पानी मिल जाता है। आ चुका है कि कुछ इलाकों में तहिलाओं को पीने का पानी लाना चाहिए लिए प्रतिदिन औसतन छोटे क्लोपीटर से भी ज्यादा का सफाई पदल तय करना पड़ता है। हालांकि सरकार द्वारा जलशक्ति अभियान के तहत हर घर को पानी मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। तिकिन इस तथ्य को भूल न जरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि देश में 2030 तक पानी का नस्तर देखनी हो जाएगी और 2050 तक यह चार गुना बढ़ जाएगी तथा जल संकट का देश हो सकल घरेलू उत्पाद पर छह फीसदी तक असर पड़ सकता है। भारत

पानी का कमा का संकट लगातार किस कदर गहरा रहा है, इसका अनुमान सरकार द्वारा संसद में दी गई उस जानकारी से भी लगाया जा सकता है, जिसमें बताया गया था कि वर्ष 2001 और 2011 में भारत में जल उपलब्धता प्रति व्यक्ति क्रमशः 1816 और 1545 घन मीटर थी, जो अब 1480 घन मीटर से भी कम रह जाने का अनुमान है। हायप्रदूषण मुक्त सांस्कैल पुस्तक के मुताबिक भूमिगत जल का अंधार्धुद्ध दोहन किए जाने का ही नरीजा है कि कई शहरों में भू-जलस्तर तेजी से नीचे गिर रहा है। नीति आयोग यह चेतावनी दे चुका है कि देश के 21 बड़े शहरों में भू-जल का स्तर आने वाले समय में शून्य तक पहुंच सकता है। जल संकट गहराने के पीछे निदियों तथा जलाशयों के सही रखरखाव का अभाव और उनका अतिक्रमण भी कुछ अहम कारणों में शामिल हैं। देश की अधिकांश आवादी दूषित पेयजल का सेवन करने पर विवश है। भू-जल बोर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 1990 के बाद से भू-

चयन और चुनाव

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) में दो रिक्तियों को भरने में, हड्डबड़ी न सही लेकिन, दिखाई गई तेजी की उचित ही आलोचना हुई है। इस बहु-सदस्यीय निकाय को चुनाव आयुक्त (ईसी) अरुण गोयल के इस्तीफे के कुछ ही दिनों के भौतर दो नए सदस्य मिल गए। खुद अरुण गोयल की नियुक्ति भी भारत में चुनावों का संचालन और उसकी निगरानी करने वाले इस आयोग के सदस्यों के चयन की सही मायने में एक स्वतंत्र प्रक्रिया की व्यवस्था से संबंधित एक सर्विधान पीठ में चल रही सुनवाई के बीच में हुई हुई थी। आलोचकों का यह कहना गलत नहीं है कि मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और अन्य चुनाव आयुक्तों के चयन की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाला अधिनियम सर्विधान पीठ के मार्च 2023 के फैसले में परिकल्पित स्वतंत्रता की कस्टोटी पर खरा नहीं उतरता मालूम होता है। चुनाव आयुक्तों का चयन ऐसे समय में हुआ जब इस अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई होने वाली थी। इन दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में, व्यक्तिगत कारणों से दिया गया श्री गोयल का इस्तीफा अस्पष्ट बन गया है। यह बेहद गंभीर चिंता का विषय है कि एक चुनाव आयुक्त, जिसका कार्यकाल पूरा होने में अभी कुछ साल बाकी थे, ने आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव कार्यक्रम को अंतिम रूप देने से कुछ दिन पहले इस्तीफा देने का विकल्प चुना। कहने की जरूरत नहीं कि चुनाव आयुक्तों के चयन की प्रक्रिया से जुड़ी चर्चा का दो नए चुनाव आयुक्तों सर्वश्री ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधु की योग्यता या उपयुक्तता से कोई लेना-देना नहीं है। असली समस्या उस कानून में निहित है जिसे संसद द्वारा पिछले साल सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह सवाल उठाये जाने के बाद परित किया था कि सर्विधान की स्थापना के बाद से अनुच्छेद 324 के प्रावधानों के तहत आवश्यक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को निर्धारित करने वाला कोई कानून क्यों नहीं है।



जैव उर्वकों से बढ़ती है फसल की गुणवत्ता

फसल उत्पादन में उर्वरकों की भूमिका विशेष महत्वपूर्ण है। अधुनिक सद्धन खेती में रासायनिक उर्वरकों तथा अन्य कृषि रसायनों के द्वारा प्रतिदिन बढ़ते हुए असंतुलित प्रयोग से भूमि की संरचना तथा उर्वरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस बात ने हमें यह सोचने के लिए चिंता कर दिया है कि हम प्रकृति के इस महत्वपूर्ण संसाधन भूमि की उर्वरता संरचना तथा पर्यावरण को लाम्बे समय तक कैसे बचाये रखें।

दूसरी ओर विश्व व्यापार संगठन में भारत का प्रब्रेश होने से हमारे आगे न केवल अधिक फसल उत्पादन करने की बल्कि उच्च गुणवत्ता बनाए रखने की भी चुनौती है। जैव उर्वरकों को पूरक के रूप में प्रयोग करने से रासायनिक उर्वरकों की क्षमता बढ़ती है साथ-साथ फसलों की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में भी वृद्धि होती है।

क्या है जैव उर्वरक?

पर्यावरण के संरक्षण, भूमि की संरचना तथा उर्वरता को बचाए रखते हुए अधिक उत्पादन के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने ऐसे जीवाणुओं के उर्वरक तैयार किये हैं जो वायुमण्डल में उपस्थित नत्रजन को पौधों को उपलब्ध कराते हैं तथा भूमि में स्थिरीकरण कर पौधों को उपलब्ध कराते हैं। ये जैव उर्वरक दलहनी फसलों जैसे अरह, मूंग, उर्द, चना, अदि पौधों को लाम्बे समय तक कैसे बचाये रखें।

यह जैव उर्वरक के लिए यह ध्यान रखना चाहिये कि ये फसल विशेष के लिए अलग-अलग होते हैं और फसल का नाम पैकेट पर अंकित होता है। इन्हे रासायनिक उर्वरकों के पूरक के रूप में प्रयोग करने से हम बहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं।

कृषक भारती को आपरेटिव लिमिटेड (कृषकों द्वारा उत्पादित राइजोबियम कल्नर, एजेटो बैक्टर, एसीटो

बैक्टर और पी.एस.एम. उपयोगी जैव उर्वरक हैं।

राइजोबियम कल्प्य

इसके जीवाणु पौधों की जड़ों में गांठ बनाकर रहते हैं तथा वायुमण्डल में उपस्थित नाइट्रोजन को शोषित कर भूमि में स्थिरीकरण कर पौधों को उपलब्ध कराते हैं। ये जैव उर्वरक दलहनी फसलों जैसे अरह, मूंग, उर्द, चना,

प्रयोग में लाया जाता है। इसके जीवाणु पौधों की जड़ क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से रहते हुए वायुमण्डल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर पौधों को उपलब्ध कराते हैं।

एसीटो बैक्टर

यह जैव उर्वरक गन्ने की फसल के लिए उपयुक्त पाया गया है जो गन्ने की फसल के



मटर, मसूर, सोयाबीन आदि फसलों में उपयोग में लाये जाते हैं। प्रयोग के लिए यह ध्यान रखना चाहिये कि ये फसल विशेष के लिए अलग-अलग होते हैं और फसल का नाम पैकेट पर अंकित होता है।

एजेटो बैक्टर

यह जैव उर्वरक सभी अनाज गेहूं, जौ, जई ज्वार, बाजरा, मक्का, धान, सब्जी की फसलों, फूलों तथा अन्य फसलों जैसे गन्ना, कपास, तम्भाकू एवं पटसन आदि में

लिए नत्रजन वाले उर्वरकों की लागभग 25-30 प्रतिशत की बचत करने में सहायक होता है, इसके प्रयोग से गन्ने की फसल में प्राप्त होने वाली चीजों के परत में 1-2 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है।

पी.एस.एम.

भारत की 80 से 90 प्रतिशत भूमि में फास्फोरस तत्व की पूर्ति हेतु कमी पाई जाती है। भूमि में फास्फोरस तत्व की पूर्ति हेतु प्रयोग किये जाने वाले उर्वरकों की मात्रा का लागभग 35-

40

प्रति.हे.

की आवश्कता पड़ती है।

जड़ उपचार

विधि

प्रति.हे. की आवश्कता पड़ती है।

यह विधि रोपाई वाली फसलों में प्रयोग की जाती है।

इस विधि में 1-2 किग्रा जैव उर्वरकों को 10-20 लीटर पानी में घोल बनाकर उपयोग प्रैक्टिक के लिये रोपाई हेतु पौधों को रोपाई से पूर्व 10 मिनट के

लिये जड़ों को ढुकोकर रोपाई की जाती है।

जैव उर्वरकों के प्रयोग ने सावधानियाँ

यह जीवित जीवाणुओं का भ्रिष्ट है, इसलिए इन्हें तेज

धूप, उच्च तापक्रम से संदेह बचाये रखें, अन्यथा उनके जीवाणु मरने शुरू हो जाते हैं।

भार्याओं में भांडारण के लिये मकान के काने में रेत के अन्दर घड़े में रखें।

रेत पर पानी छिड़कर कर भांडारण करें। इस प्रकार अधिक

तापक्रम के प्रभाव से जैव उर्वरकों को बचाया जा सकता है।

प्रयोग की विधि अवश्य ताकि जैव उर्वरक की पूर्ति हेतु अवस्था में परिवर्तित कर पौधों को उपलब्ध कराता है।

यह सभी प्रकार की फसलों में उपयोग किया जा सकता है।

बीज उपचार

इस विधि द्वारा राइजोबियम, एजेटो बैक्टर एवं

पी.एस.एम. जैव उर्वरकों का प्रयोग दलहन की फसलों, गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा, राई, सरसों, तिल, सूजमुखी आदि फसलों में किया जाता है।

इस विधि में एक पैकेट का घाल लगभग 200-500 मिली. पानी में बनाकर 10

किलो बीज के ऊपर एक साथ छिड़क कर हाथ से अच्छी

तरह मिलायें ताकि जैव उर्वरक की एक पतली परत बीज के सभी दानों पर बन जायें।

उपचार के तुन्त बाद ध्याया में सुखाकर बीज की बुवाई कर दें।

भूमि उपचार

इस विधि द्वारा एजेटो बैक्टर, एसीटो बैक्टर एवं

पी.एस.एम. जैव उर्वरकों का प्रयोग सभी खाद्यान्तों की

फसलों, गन्ना, तिलहन फसलों, सब्जी फसलों, फूलों आदि में किया जा सकता है।

इस विधि में जैव उर्वरकों की लागभग 2-5 किग्रा। मात्रा को 100 किलो.

अच्छी प्रकार सड़ी गोबर की खाद्य या कम्पोस्ट में मिलाकर खेत

की तैयारी के समय अनितम जुताई से पूर्व खेत में एक

साथ छिड़क कर मिट्टी में मिला।

यह जैव उर्वरकों को सड़ी नमी युक्त गोबर की खाद्य अथवा कम्पोस्ट खाद्य के साथ मिलाकर

प्रयोग करने से ही बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं।

कृषकों द्वारा हीरी संयंत्र (गुजरात) वाराणसी संयंत्र (उत्तर प्रदेश) लांचा संयंत्र (महाराष्ट्र) में कुल 650 मीट्रिक टन

जैव उर्वरकों का उत्पादन किया जाता है।

ये जैव उर्वरक कृषक भारती सेवा केंद्रों एवं सहायता समितियों से प्राप्त

किये जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृषकों

नजदीकी प्रतिनिधि से भी सम्पर्क किया जा सकता है।



